International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बिहार विधान सभा चुनाव- 2025 : समग्र विश्लेषण

डॉ अखलाख अहमद

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), अनजबित सिंह महाविद्यालय, बिक्रमगंज (रोहतास) बिहार

शोध-सारांश

विश्व को लोकतंत्र का संदेश देनेवाला बिहार में विधान सभा चुनाव 6 एवं 11 नवम्बर 2025 को दों चरणों में संपन्न हुआ | इस चुनाव की विशेष महता थी क्योंकि केंद्र सरकार की स्थिरता इसके परिणाम से गहरे रूप में प्रभावित होती | इस बार के चुनाव में भी जाति एवं धर्म की राजनीति के कयास पूर्व की भांति विश्लेषकों ने लगाए थे | विकास पुनः सिर्फ मुखौटा ही साबित हो एवं ध्रुवीकरण की राजनीति केंद्र में रहे, ऐसा कुछ दल एवं प्रमुख गठबंधन का प्रयास था | इससे इतर विपक्ष पुराने एम.वाई .समीकरण एवं एंटी इनकोमबेंसी के लाभ की उम्मीद कर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा | तीसरी एवं नयी पार्टी ने नए बिहार के सपने के साथ आजमाइश की | उल्लेखनीय है कि इस चुनाव के परिणाम भी एम.वाई .समीकरण के अनुरूप ही हुए किन्तु एम.वाई .का अर्थ मुस्लिम एवं यादव न होकर महिला एवं युवा हो गया | इस शोध पत्र में में बिहार बिधन सभा चुनाव- 2025 के चुनावी गतिविधियों के आरम्भ से लेकर अंत तक के राजनीतिक दलों की रणनीति, सियासी दाँव, प्रभावी कारकों एवं परिणामों का निष्पक्ष विश्लेषण किया जायेगा |

कीवर्ड : विशेष, स्थिरता, धर्म एवं जाति, ध्रुवीकरण,सियासी , प्रभावी कारक

परिचय :

लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला चुनाव है । बिना आम चुनाव के लोकतंत्र केवल एक संकल्पना बनकर रह जाता है । लोकतंत्र के शाश्वतता की परख, शासन की औचित्यता, वैधानिकता, प्रमाणिकता और सबसे बढ़कर सरकार के क्रियाकलापों की समाज रूपी प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु चुनाव की तिथियों का सरकारी ऐलान होते ही बिहार राज्य में चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हुई | बिहार विधानसभा चुनाव-2025 का बिगुल बजते ही राज्य पूरे उत्साह से चुनाव हेतु सक्रीय दिखा | सभी प्रमुख राजनीतिक दल और गठबंधन अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने लगें । चौक-चौराहों पर बहसें गूंजने लगी , सत्ता पक्ष जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने लगा तो विपक्ष कमियों को उजागर करने में जुटा रहा । ये सब चुनावी लोकतंत्र की सामान्य धड़कनें हैं । विश्व को लोकतंत्र

का संदेश देनेवाला बिहार में आदर्शों के अनुरूप, लोकतान्त्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता, सशक्तता तथा सरकार के कार्यकाल की पूर्णता के उपरांत चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न हुआ ।

शोध उद्देश्य एवं विधि :

प्रस्तावित शोध पत्र में बिहार विधान सभा 2025 के चुनाव की आचार संहिता के क्रियान्वयन के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों एवं गठबंधन की क्रियाशीलता, उनकी रणनीति, सियासी दांव, आपसी तनाव, दलीय लोकतंत्र की

स्थिति एवं चुनाव परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण किया जायेगा |

इस शोध पत्र को तैयार करने में व्याख्यात्मक एवं आनुभविक शोध विधि, क्षेत्र भ्रमण, जनमत सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं मीडिया रिपोर्ट का प्रयोग किया गया है | प्राथमिक आंकड़े : 12 जिलों के भ्रमण, 42 गहन साक्षात्कार एवं 1800 मतदाताओं का संरचित सर्वेक्षण तथा द्वितीय आंकड़ों के लिए चुनाव आयोग का अधिकारिक रिपोर्ट, CSDS –लोकनीति सर्वेक्षण, मीडिया से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है |

चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा में तल्लीन हो गये | चुनाव के आरंभिक दौर में देखा जाये तो सियासी दबाव प्रमुख गठबंधन एवं राजनीतिक दलों में साफ परिलक्षित होता है | दोनों प्रमुख गठबंधन सीट बटवारे की समस्या से जूझ रहें थे | सूत्रों की माने तो एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी एवं चिराग पासवान जैसे सहयोगी दबाव बना रहे थे | चिराग पासवान को बड़े पद चाहिए तो मांझी ने दिल्ली –झारखण्ड जैसे धोखे से बचने की चेतावनी दी , हालाँकि बीजेपी एवं जेडीयू में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है | महागठबंधन में अपेक्षाकृत आंतरिक दबाव अधिक है | कांग्रेस का अधिक सीट का दावा तो राजद द्वारा 243 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ने की विपक्ष के नेता की घोषणा ने दबाव को और बढ़ा दिया है | इस सन्दर्भ में सम्बंधित दल के प्रवक्तावों ने सफाई देते हुए डैमेज कंट्रोल किया कि विपक्ष के नेता का आशय सभी सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के लड़ने से है | जन सुराज की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने जेडीयू पर दबाव बढाया | जेडीयू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार से उपमुख्यमंत्री का पद माँगा जा रहा है | सियासी दबाव बिहार चुनाव को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि गठबंधन की स्थिरता एवं वोटर विश्वास का प्रतीक बनता हुआ दिखाई दिया है |

दबाव सिर्फ आंतरिक ही नहीं ,वाह्य दबाव एवं चुनौतियाँ भी निरंतर दृष्टिगत हुआ है | महागठबंधन का एक बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यकों का विशेषकर मुस्लिम वोटरों का है | राष्ट्रीय राजनीति में एआईएमआईएम द्वारा मुस्लिमों का हिमायती बताकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसकी भूमिका ने मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित किया है | इतना ही नहीं पिछले बिहार के चुनाव में इस दल के द्वारा मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर जीत दर्ज करना, अल्पसंख्यकों के ओवैसी प्रेम को स्पष्ट करता है | इस दल द्वारा महागठबंधन में शामिल करने का दबाव निरंतर प्रयास किया | ऐसे में एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को बचाना एवं ओवैसी के प्रभाव को कम करने का यह दुहरा दबाव महागठबंधन पर था | यह दल सड़क पर उतरकर गठबंधन में शामिल होने की स्पष्ट मांग कर रहा था | ऐसे यदि यह दल

गठबंधन में शामिल होने में सफल होता तो सीट शेयरिंग की समस्या और जटिल हो सकती थी | यदि शामिल नहीं होता तो भी चुनाव में यह दल मुस्लिम मतदाताओं के बीच गठबंधन को मुस्लिम विरोधी एवं स्वयं को हितैसी बताकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है |

बिहार चुनाव की सबसे अधिक चर्चा दिल्ली के गलियारों में थी | राजनीतिक एवं चुनाव विश्लेषकों से एक कॉमन सवाल पूछे जा रहें थे कि जनसुराज का क्या ? दरअसल इस सवाल के पूछे जाने के पीछे लोगो द्वारा इतिहास दुहराने की संभावना की परिकल्पना है | दरअसल 2013 में दिल्ली में एक पार्टी का गठन हुआ था | वो पार्टी 10 वर्षों तक दिल्ली के सत्ता में रही | पंजाब में उसका सत्ता है | आज वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल है | अब आम जन को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनसुराज इस इतिहास को दुहरा सकती थी | इस तथ्य के प्रभाव से दोनों गठबंधन के दबाव में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है |

बिहार चुनाव से पूर्व राजनीतिक तापमान शिखर पर उस समय पहुँच गया जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से ठीक पहले निश्चित टाइम फ्रेम में मतदाता सूची पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया | विपक्षी गठबंधन ने यह आरोप लगाया की उनके वोट बैंक को टारगेट करके या मतदाता सूची से लक्षित मतदाता का नाम हटाने के लिए सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है | विपक्ष का आरोप था कि अभी आधा बिहार बाढ़ जैसी प्राकृतिक समस्या से जूझ रहा है एवं जो दस्तावेज मांगे जा रहें है वो उचित नहीं है | मामला माननीय सर्वोच्च न्यायलय तक पहुँचा | विषय की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने सुनवाई की | न्यायलय ने पुनरीक्षण कार्य पर रोक लगाने से इंकार किया कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है | इस सन्दर्भ में कुछ मार्गदर्शन तथा 12 वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की मान्यता दी | यह मामला और अधिक तब गंभीर हो गया जब अल्पसंख्यक समुदाय को इसे कहीं न कहीं एनआरसी का पूर्वाभ्यास बताया जाने लगा | चुनाव आयोग ने अपनी क्षमता एवं निष्पक्ष चुनाव की दृढ इच्छा के अनुपलार्थ इस कार्य की पूर्णता की ओर अग्रसर है | जो भी हो पक्ष एवं विपक्ष इस मुद्दें पर दबाव में रहें हैं |

बिहार चुनाव से कुछ दिन पूर्व वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा | नीतीश कुमार एवं चंद्राबाबू नायडू को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में घोर नाराजगी दिखी | पटना के गाँधी मैदान में बड़ी रैली हुई | इस रैली से बिहार के सत्ताधारी गठबंधन थोड़े समय के लिए वृहत दबाव में होने की आशंका लगायी गयी | इतना ही नही दोनों गठबंधन के लिए सीमांचल में पप्पू यादव की पार्टी सिरदर्द साबित हो सकती है |

इन सब के बावजूद नीतीश कुमार जो न केवल वर्तमान सरकार के मुखिया है वरन् उन्होंने अपनी छवि समाज सुधारक के रूप में स्थापित करने में सफलता अर्जित की है | शराब बंदी, सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण, महिला विकास पर कई योजना, भ्रष्टाचार के प्रति जीरों टॉलरेंस की नीति, पिछड़े समाज के लिए प्रयास, महादलित समुदाय को मुख्यधारारा में लाने का प्रयास, सरकारी नौकरियों की लगातार भर्ती के अलावा 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा से विपक्ष पर अतिरिक्त दबाव बढाया तो एंटी इन्कोम्बेंसी के प्रभाव से सत्ता पक्ष की चिंता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है |

आम तौर से उत्तर भारत के चुनावों में जाति एवं सम्प्रदाय की भूमिका प्रमुख होती है | हमारी वर्तमान सामाजिक संरचना में इनके प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता | चुनाव के आरंभिक दिनों में तो सिर्फ दबाव दिखा जो दल अथवा गठबंधन के अनुरूप दबाव को कम कर व्यवहारिक मुद्दों के साथ वोटरों को एकत्रित करने में सफल हुए |

चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई | आयोग के निर्देश के अनुपालार्थ प्रशासन चुनावी मोड में आई ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके | तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ने लगी | वातावरण के अनुरूप मुख्य राजनीतिक दल संयम वरतते हुए रणनीतिक दृष्टि से आगे बढ़े | इस बीच नए खिलाड़ी के रूप में पहली बार इंट्री करनेवाली पार्टी जनसुराज ने अपने स्तर से चुनावी वातावरण में गर्माहट लाने में सफलता पायी है | मतदान और परिणाम तो बाद की बात है, अभी जनसुराज की स्थिति, रणनीति, क्रियाकलाप, प्रभावशीलता, दलीय चमक की धमक, अपेक्षाएं आदि चर्चा के केंद्र में रहा है | समय के साथ दलों की सक्रियता, प्रतिस्पर्धा में बदली | राजनीतिक सरगर्मी का यह परिदृश्य निश्चय ही दिलचस्प हुआ है | उल्लेखनीय है कि बिहार चुनाव पर पडोसी राज्यों की नज़र तो थी ही साथ ही दिल्ली की भी निगाहें टिकी रही है |

नया दल, पूरा बल, वर्तमान सफल, भविष्य उज्जवल, के अनुरूप जनसुराज प्रथमतः सत्ताधारी गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं पर बड़े आरोप यथा : अवैध डिग्री और सम्पति का खुलासा करके राजनीतिक वातावरण में गर्माहट ला दी | इस प्रकरण से आम जन का ध्यान आकर्षित करने में उन्हें सफलता मिली है | इस दल का प्रयास था कि भ्रष्टाचारी बेनकाब हो एवं भ्रष्टाचार का मुद्दा स्वतः केंद्र में आ जाये | राजनीतिक रोमांच बढ़ा है किन्तु दलीय प्रभाव की समीक्षा नहीं हुआ है | आम जनता तो शुरुआत में सुषुप्त अवस्था में दिखी जो यह प्रमाणित करता है कि विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बिहार में लोकतंत्र की जड़े सतही नही वरन गहरी हो चूकी है | इस दल की कार्ययोजना क्या है, यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है लेकिन इनका मानना है की बिहार की बदहाली, पिछड़ापन,पलायन जैसी समस्याओं के लिए अब तक के सत्ताधारी राजनीतिक दल जिम्मेदार है एवं हमारी पार्टी सरकार बनाकर इससे निवृति दिला देगी | कुछ जगहों पर कंट्रोवर्सी भी दिखी , जैसे आरम्भ में यह कहना कि सरकार बनाने के लिए मुसलमानों की कोई जरुरत नहीं है फिर मुसलमानों को बिहार बदलाव के लिए विशेष आमंत्रण देना, पटना के गाँधी संग्रहालय में मुस्लिमों को हदीश की रौशनी में बदलाव हेतु प्रेरित करना , भावनात्मक रूप से समर्थन पाने का प्रयास एवं व्यवहार में राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश से नीतिगत विरोधाभाष स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है |

इस नए दल के अनुसार इसका सबसे सबल पक्ष इसका क्लियर विज़न है | बिहार में बदलाव, भ्रष्टाचार का समापन, धर्म और जाति विहीन राजनीति , झूठे एवं फरेब नेताओं पर शिकंजा, नए चेहरों के साथ चुनाव में जाने के साथ-साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, समेत सभी क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का समाधान इनकी प्राथमिकता है | इन सभी मुद्दों का एक झटके में समाधान सुनने में भले ही अच्छा लगता हो किन्तु काल्पनिक अधिक है | वैसे स्टिंग आपरेशन में इनकी भूमिका की तारीफ करनी होगी |

उपरी तौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति के दो मुख्य कारक अभी भी हैं – जाति एवं संप्रदाय है | ये कारक सभी प्रमुख दलों की रणनीति को प्रभावित करते रहें हैं | महागठबंधन का पूरा प्रयास है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न होने पाए, वहीं धर्म के नाम पर मत का अनुरोध भी करने वाले दल भी मैदान में थे | इस पृष्ठभूमि में एआईएमआईएम की भूमिका दिलचस्प हो जाती है | इस चुनाव में इनको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा | इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इतिहास दुहराने अर्थात सिमांचल में पूर्व की भांति परिणाम,कम से कम 5 सीटों को प्राप्त करने का है | इन्हें यह भी भय है कि कहीं इनकी सक्रियता से पूर्ण ध्रुवीकरण न हो जाये, क्योंकि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इन्हें भी जिम्मेदार माना जाता हैं | इस दल को इस तथ्य का आभास पूर्व से था तभी तो महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश इनके द्वारा किया गया | यदि ध्रुवीकरण होता तो सत्ताधारी गठबंधन की बड़ी सहयोगी का काम आसान हो जाता | मौके के साथ बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलने से चुकती नहीं | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आज के सन्दर्भ में मुस्लिम अपने विकास के लिए नहीं बल्कि किसी खास दल को सत्ता में आने से रोकने के लिए मतदान कर रहें है | कुछ भी हो एआईएमआईएम सिमांचल में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाकर किंगमेकर बनने की कोशिश में रही |

सत्ताधारी गठबंधन ने कोई भी दांव छोड़ा नहीं है | डबल इंजन सरकार, सड़क, बिजली, पानी कल्याणकारी योजनाओं और सबसे बढ़कर वर्तमान में जीविका और अन्य समूह को सीधे आर्थिक लाभ पहुचाया गया है। बैंकों में महिलाओं की लम्बी कतारें निकासी हेतु देखी गई है | कॉपी, बैग, छात्रवृति की रकम ,ये सभी आर्थिक सहयोग बड़ी भूमिका निभाए हैं | तालीमी मरकज, टोला सेवक को सीधे लाभान्वित सत्ताधारी गठबंधन ने लगभग मजबूत पकड़ बनायीं है | विपक्ष की डोमिसाइल नीति, फ्री बिजली एवं रोजगार पर भी हाल के दिनों में बड़े फैसले लेकर मौके पर चौका मारने का कार्य किया गया है | सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने इन्हें अतिरिक्त लाभ पहुंचाया है | इस गठबंधन की बड़ी सहयोगी बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कहीं न कहीं इस दल का बड़ा दांव हो सकता था किन्तु ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला |

विपक्षी गठबंधन एंटी इन्कोम्बेंसी, बेरोजगारी, सभी जाति एवं धर्मों का सम्मान, युवा का आइकॉन तेजस्वी का नेतृत्व,युवा आयोग के गठन का वादा, मुफ्त शिक्षा एवं परीक्षा,युवाओं के पलायन को रोकने का भरोसा और सबसे बढ़कर तेजस्वी का यह कहना कि –20 महीने का समय दे, बिहार का नक्शा बदल देंगे , राजनीतिक माहौल को प्रतिस्पर्द्धी बनया |

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चुनाव के मुद्दे अब बदलते रहें हैं, फलतः चुनावी परिदृश्य बदलना भी स्वाभाविक था | सच में परम्परागत मुद्दे यथा: बिजली, सड़क, पानी, ग्रामीण विकास, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, कानून-व्यवस्था अब प्रासंगिक नहीं प्रतीत हुए हैं | बिहार एवं बिहारी अस्मिता का सम्मान,युवा केन्द्रित नीति, पलायन पर रोक और तकनीक आधारित सामाजिक विकास के लिए नए दल जहाँ ध्यान आकर्षित किये हैं वहीं इसी मार्ग के अनुरूप सभी दल रणनीति को अंतिम रूप देने के प्रयासरत दिखे |

इस बार असली सवाल यह है: इस बार मतदान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? सर्वे अपनी-अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स धुंधली हैं। फिर भी, चुनावी परिदृश्य की तेजी से बदलती तस्वीर से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारतीय सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव है, जो राजनीति को भी आकार देता है। उत्तर भारत में राजनीति अक्सर अगड़ी-पिछड़ी जातियों के द्वंद्व के रूप में उभरती है। बिहार में टिकट वितरण से लेकर गठबंधन तक, जातीय समीकरण प्राथमिकता पाते हैं। कुछ दलों को विशिष्ट जातियों का प्रतिनिधि माना जाता है—जैसे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को यादव-मुस्लिम बेस वोट, और जनता दल (यूनाइटेड) [जद(यू)] को कुर्मी-कोइरी आधार। 2025 के चुनाव में भी यही जातीय ध्रुवीकरण राजनीति की शुरुआत करेगा, यह संभावना प्रबल है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'सोशल इंजीनियरिंग' की समझ ने बिहार की राजनीति को नया आयाम दिया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 'पचपनिया वोट' है—55 अत्यंत पिछड़ी जातियों का समूह, जिसमें विन्द, धानुक, निषाद, कुम्हार, कोहार, चौरसिया आदि शामिल हैं। ये साइलेंट वोटर हैं | किसी एक विधानसभा क्षेत्र में इनकी संख्या सीमित हो सकती है, लेकिन समूहबद्ध रूप से इनका प्रभाव निर्णायक होता है । जनसंख्या के लिहाज से ये 20-25% वोट बैंक बनाते हैं। नीतीश कुमार ने इनकी महत्वपूर्णता को पहचाना और इन्हें केंद्र में रखकर नीतियां गढ़ीं। बिना इनके, जद(यू) का वोट शेयर महज 2-3% रह जाता। 2020 के चुनावों में इनका योगदान NDA की जीत का आधार बना। इस बार भी यदि ये वोट एकजुट होकर सत्ता पक्ष मजबूत किया ; अन्यथा विपक्ष को अप्रत्याशित लाभ हो सकता था । इसके साथ ही जदयू का बीजेपी गठबंधन में रहते हुए भी पिछड़े मुसलमान उससे सहानुभूति रखते है एवं इस पार्टी के लिए वोट भी करते हैं | नीतीश कुमार की पसमांदा मुसलमानों के विकास के लिए जो सार्थक प्रयास किये है उसका सकारात्मक परिणाम सामने आता है | नीतीश अपनी छवि से मुसलमानों के मत भी प्राप्त करते रहें हैं एवं इस बार भी ऐसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता |

महिला मतदाताओं की भूमिका भी अब निर्णायक है। आंकड़ों के अनुसार, बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो चुका है—2020 में यह 59.2% के मुकाबले 59.7% रहा। समाजशास्त्री इसे नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति का फल मानते हैं, जो ग्रामीण महिलाओं की छवि में सुधारक के रूप में स्थापित हुई। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण, छात्रवृत्तियां, पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, और शिक्षक भर्ती में विशेष प्रावधानों ने इन्हें सशक्त किया। कुछ विद्वान पुरुष पलायन को भी इसका कारण बताते हैं, लेकिन आंकड़े इसे पूर्णतः सत्यापित नहीं करते। महिलाओं का यह सशक्तीकरण 2025 में फिर से वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया है ।

आधुनिक चुनावी युद्ध अब डिजिटल मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया और आईटी सेल्स सक्रिय दिखी —घटनाओं को पक्ष-विपक्ष के चश्मे से पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। किसी भी घटना को अपने दलों के समर्थन एवं विरोधी दल या गठबंधन के विरोध में कैसे वातावरण तैयार किया जाये, इसके लिए दिन –रात लगे रहते हैं | युवाओं के पास स्मार्टफोन होने से सोशल मीडिया ही सत्य का स्रोत बन गया है। जो दल का आईटी

नेटवर्क मजबूत, उसका प्रभाव गहरा। 2020 में फेक न्यूज और वायरल कैंपेन ने कई सीटें पलट दीं; इस बार भी युवा वोट (बिहार की 35% आबादी 18-35 वर्ष के बीच) इसी माध्यम से प्रभावित हुए हो इससे इंकार नहीं किया जा सकता है ।
समकालीन मुद्दे भी वोट शेयर के लिए अहम् साबित हो सकते हैं। विपक्ष एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को 'वोट चोरी' का हथियार बता रहा है। चुनाव आयोग की इस पहल से 65 लाख नामों का विलोपन हुआ, जिसे विपक्ष 'अलोकतांत्रिक' करार दे रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, याद दिलाते हुए 'चौकीदार चोर है' जैसे पुराने नारों को। लेकिन केंद्र की रैलियां और घोषणाएं इनका जवाब दे सकती हैं। पिछले चुनाव का अनुभव यह बताता है कि प्रधानमंत्री की रैली एवं घोषणाएं चुनावी परिदृश्य को अपने सत्ताधारी दल के लिए लाभप्रद हुए हैं|

बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी है। युवा बेरोजगारी दर 20% से ऊपर होने के बावजूद, सरकार तेजी से भर्तियां कर रही है—शिक्षा विभाग में TRE-1 से TRE-5 तक की प्रक्रिया, पुलिस-स्वास्थ्य विभागों में रिक्तियां भरना, और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर भर्ती। आलोचना तो होगी कि ये चुनावी वर्ष के 'लॉलीपॉप' हैं, लेकिन नई पीढ़ी वर्तमान से प्रभावित होगी। ये कदम सकारात्मक वोटिंग को प्रेरित किये है ।
इनके अलावा, एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर, जन सुराज जैसे तीसरे विकल्प का युवा आकर्षण जो युवाओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है | यह दल आप जैसी राजनीतिक दल की सफलता से कहीं न कहीं उत्साहित है एवं ऐसी सोंच है कि सत्ता का सूत्रधार हो सकता हैं | एक वर्ग का ऐसा मानना भी है कि यह पढ़े –लिखे लोगों की ऐसी पार्टी है जिसे बिहार का नेतृत्व सौपा जाना चाहिए | हालाँकि बिहार विधान सभा के उप चुनाव में इस दल ने बीजेपी गठबंधन को लाभ पहुचायां था | एआईएमआईएम की भूमिका छोटे रूप में ही सही सिमांचल में इसका प्रभाव तो होगा ही साथ ही अन्य जगहों पर मत ध्रुवीकरण में भी इसकी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है| विचारधारात्मक टकराव, और 1.74 करोड़ नए मतदाताओं का प्रवेश भी महत्वपूर्ण हैं। EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और गुलाबी पेपर का उपयोग मतदान को सरल बनाएगा।

अंततः, इन सभी कारकों का समन्वय ही तय किया कि बिहार की बागडोर किसके हाथों सौंपी जाएगी। लोकतंत्र का असली सौंदर्य यही है—मतदाता सर्वोपरि है । लोकतंत्र का यही तकाज़ा भी है कि मतदाता अंततः सबसे बड़ा कारक सिद्ध होता है।
बिहार विधान सभा चुनाव छिट- पुट अप्रत्याशित घटनाओं के साथ सफलता पूर्वक संपन्न हुआ | स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित की है | चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 66.91% मतदान हुआ है | इसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.91रहा जबकि महिलाओं का मतदान 71.6% दर्ज किया गया | स्पष्ट है पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 8.8 % मतदान अधिक किया है | यह स्थिति चुनाव आयोग की सकारात्मक भूमिका, प्रशासनिक कुशलता, राजनीतिक जागरूकता, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति चिंता से मुक्ति आदि को दर्शाता है | प्रायः चुनाव परिणाम के बाद

सत्ताधारी दलों को प्रशासन की मदद, चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका पर प्रश्न चिन्ह, EVM पर सवाल और मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप विपक्ष द्वारा लगाये जाने का फैशन बन चुका है |

अब सीधे-सीधे चुनाव परिणाम की बात की जाये तो बिहार में राजग गठबंधन की जीत की सुनामी का कारण जंगल राज की वापसी का भय कदापि नहीं है | युवाओं का एक बड़ा तबका तो उस फेज को देखा भी नही था | ऐसे में सिर्फ जंगल राज वापसी का भय दिखाकर इतना बड़ा जनादेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है | दरअसल इस जीत का बड़ा कारण यह है कि सत्ताधारी गठबंधन द्वारा जो विकास की अविरल धारा प्रवाहित है उसपर विराम न लगे | अब मतदान भय से नहीं वरन् आशा से किया जा रहा है | आज समाज के प्रत्येक तबके को, प्रत्येक स्तर पर अपना अधिकार प्राप्त ही नहीं है वरन् उसका निर्विवाद रूप अनुप्रयोग करने में बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है | हालाँकि इसके पीछे डिजिटल कार्य संस्कृति भी एक कारण हो सकता है |

चुनाव परिणाम अप्रत्याशित नहीं है | सोशल इंजीनियरिंग के प्रणेता एवं दूरगामी सोच रखनेवाले नीतीश कुमार की समझ राजनीति से कहीं अधिक सामाजिक है | बिहार में जिसे पचपनिया वोट कहा जाता है आज उसमें 112 जातियों सम्मिलित हो चुकी है | यह वृहत आकार ले चुका है | ये वोटर साइलेंट ही नहीं पूर्णतः संगठित है | नीतीश कुमार ने इन्हें निर्णायक मतदाता के रूप में पहचान कर इनके प्रति गहरी संवेदना रखते हुए, इनकी सहानुभूति प्राप्त की है | ये ऐसे मतदाता है जो आज पूर्णतः जागरूक एवं आक्रामक हो चुके है ,किन्तु चौक-चौराहों पर राजनीतिक विमर्श में ये सहभागी नहीं होते हैं |

नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव बड़े ही संयमित, सूझ-बुझ एवं संतुलित रणनीति के साथ लड़ा गया | विपक्ष के कई गंभीर मुद्दों का समाधान यथा : सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों का प्रकाशन एवं कुछ का संपादन चुनाव पूर्व ही करके सत्ताधारी गठबंधन ने जीत का नीव रख दिया था |

राजग गठबंधन के चुनावी रणनीतिकारों ने सीट बंटवारा भी बड़ी सूझ- बुझ के साथ किया | उदहारण स्वरुप इस बार चुनाव में रोहतास जिला के सभी सीटों पर जेडीयू को टिकट दिया गया, जहाँ 7 में से 6 सीट पर जीत दर्ज हुआ | पिछले चुनाव में ये सारे सीट महागठबंधन के पक्ष में रहा था | राजग गठबंधन का यह कदम आपसी तालमेल को प्रदर्शित करता है |

इस बार के बिहार चुनाव में सबसे बड़ा विपक्ष एवं कई चुनाव विश्लेषकों का सत्ता पक्ष पर आरोप आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 10000 रुपया सरकार द्वारा दिए जाने का है, जिसे राजनीतिक रिश्वत या मत खरीदने के सन्दर्भ में देखा जा रहा है | इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसा सभी को प्यारा है एवं इसके प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सीमांचल में गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, मृत्यु दर अधिक,प्रति व्यक्ति आय का कम होना एक ऐसे पृष्ठभूमि का सृजन करता है जहाँ पैसे देकर मत लेना अन्य जगहों के अपेक्षा आसान है | इसके बावजूद सीमांचल में सभी पाँचों सीटों पर एआईएमआईइएम के उम्मीदवारों का जितना कहानी कुछ और ही बयाँ करती है | यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक

बायसी सीट को छोड़कर सभी जगह मुस्लिम उम्मीदवार ही हारे है, जिनमे जेडीयू के मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल है | अब कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम है | इस सन्दर्भ में कहना है कि हारने वाले एक को छोड़कर सभी उसी धर्म के है | यदि 10000 निर्णायक फैक्टर होता तो निश्चय ही जदयू एवं उसके गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी ही विजयी होते | यह भी सत्य है कि यहाँ कई-कई मुस्लिम विकल्प उपलब्ध थे जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें मुस्लिम वोट का एकमात्र उतराधिकारी माना जाता है |

बिहार विधान सभा चुनाव 2025 की सबसे सुखद बात यह है कि कई प्रयासों के बावजूद भी धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ | ओसामा साहाब के रघुनाथपुर के चुनाव में देश गृह मंत्री समेत बड़े नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया था, किन्तु वह निष्प्रभावी रहा है | इस चुनाव की प्रकृति पर अगर विचार किया जाये तो मुसलमानों को छोड़ यादव बनाम लगभग जातियों का चुनाव रहा | यहाँ जातीय स्तर पर ध्रुवीकरण के बावजूद विकास की सही दिशा एवं सरकार की सकारात्मक एवं सर्वहित के कदम इस ध्रुवीकरण पर चादर डाल देते हैं और सबकुछ पूर्णतः लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप दृष्टिगत प्रतीत होता है |

राजग गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है जिसमें कमोबेश सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है | जबकि विपक्षी गठबंधन मूलतः यादव, मुस्लिम एवं मल्लाह के मत तक अपने को सीमित करता है | ध्यान रहे जब तालाब बड़ा होगा तो उसकी धारण क्षमता भी अधिक होगी एवं उस तालाब से पानी भी ज्यादा ही निकलेगा | तंत्र का मामूली समर्थन सत्ता को हो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता , किन्तु चुनाव परिणाम सिर्फ तंत्र के सहयोग का प्रतिफल है , ऐसा कहना बेईमानी है |

राजग की यह जीत की सुनामी राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगी | 2026 में असम, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में चुनाव होने है | युवा पलायन बेरोजगारी के सन्दर्भ में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं सीमांचल का विकास सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है |

महागठबंधन में आपसी ताल-मेल का अभाव, 243 सीट पर 255 उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना, कांग्रेस का बिहार में मृतप्राय संगठन का होना, सहनी की अनुभवहीनता, राजद के टिकट बंटवारे से उपजा असंतोष, गठबंधन द्वारा सीएम चेहरा विलम्ब से घोषित करना एवं सबसे बढ़कर महिला मतदाताओं की सहानुभूति विपक्ष के साथ होना हार का प्रमुख कारण हो सकता है | महागठबंधन को अब दीर्घकालिक रणनीति बनाकर, जनता से सीधे जुड़कर, अहम् का विसर्जन कर, आपसी ताल मेल बनाकर कर नयी परिदृश्य में नए दृष्टि से सोचने की आवश्यकता हैं |

निष्कर्ष एवं सुझाव :--

बिहार विधान सभा चुनाव – 2025 ने यह सिद्ध किया है कि जाति की राजनीति अभी भी प्रासंगिक है किन्तु विकास, महिला सशक्तिकरण तथा युवा आकांक्षाएँ अब निर्णायक कारक बन चुके है | सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत केवल 'जंगल राज के भय' से नहीं वरन् ठोस प्रशासनिक उपलब्धियों (सोशल इंजीनियरिंग एवं कल्याणकारी योजनाएँ)

एवं परिवर्तित सामाजिक समीकरणों (महिला-युवा) से समझा जाना चाहिए | इससे स्पष्ट है कि भविष्य की बिहार की राजनीति अधिक समावेशी एवं विकास-केन्द्रित होगी |

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. चुनाव परिणाम एवं मतदान आंकड़ेभारत निर्वाचन आयोग. (2025). बिहार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2025: सांख्यिकीय प्रतिवेदन. https://results.eci.gov.in
2. जगरण जोश. (2025, 14 नवंबर). बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दल एवं निर्वाचन क्षेत्रवार विजयी-पराजित उम्मीदवार.
3. एनडीटीवी. (2025, 19 नवंबर). बिहार में 66.91% मतदान; 1951 के बाद सर्वाधिक. इंडिया टुडे. (2025, 10 नवंबर). बिहार चुनाव 2025: 7.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया.
4. . जाति, धर्म एवं सोशल इंजीनियरिंगइंडिया टुडे. (2025, 17 नवंबर). बिहार 2025: जाति दरारें, विकास का स्वर, या 'सबाल्टर्न' उभार?.
5. पाई, एस. (2002). बिहार में निर्वाचक व्यवहार: जाति, धर्म एवं विकास की भूमिका. राजनीति विज्ञान पत्रिका, 7(6),
6. द गियोस्ट्राटा. (2025, 12 जुलाई). बिहार चुनाव 2025: जाति, शक्ति एवं पहचान की राजनीति.
7. न्यूज़लॉन्ड्री. (2020, 28 अक्टूबर). नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में नई सामाजिक गठबंधनों का निर्माण कैसे किया. राजनीतिक गठबंधन, नए दल एवं रणनीतियाँबिज़नेस स्टैंडर्ड. (2025,14 नवंबर). बिहार चुनाव परिणाम: एनडीए एवं महागठबंधन का प्रदर्शन.
8. एनडीटीवी. (2025, 13 नवंबर). 'बिहार जीता, अगला लक्ष्य बंगाल': गिरीराज सिंह जब एनडीए बहुमत की ओर
9. विकिपीडिया. (2025). 2025 बिहार विधानसभा लॉगसभा. (2025, 5 अप्रैल). बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रमुख मुद्दे एवं भविष्य दृष्टि
10. महिला-युवा मतदाता, डिजिटल प्रभाव एवं नीति इंडियन एक्सप्रेस. (2022, 13 अगस्त). व्याख्या: नीतीश कुमार की सफलता के तीन स्तंभ |